

---

## इकाई 13 उपनिवेश-विरोधी आंदोलन और गैर-उपनिवेशीकरण\*

---

### संरचना

#### 13.0 उद्देश्य

#### 13.1 प्रस्तावना

13.1.1 वैश्विक संदर्भ में उपनिवेशीकरण विरोधी आंदोलनों को समझना

#### 13.2 शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में गैर-उपनिवेशीकरण

13.2.1 यूएसए और गैर-उपनिवेशीकरण

13.2.2 यूएसएसआर और गैर-उपनिवेशीकरण

#### 13.3 विश्व राजनीति में गैर-उपनिवेशीकरण का प्रभाव

13.3.1 नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं का पुनर्खांकन

#### 13.4 उपनिवेशीकरण विरोधी आंदोलन और विदेश नीति के निहितार्थ — भारतीय संदर्भ

13.4.1 उपनिवेशिक अतीत और इसकी प्रासंगिकता

13.4.2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता से पहले विदेशी संबंध

13.4.3 विश्व तक पहुँचने का प्रयास और एकजुटता का प्रदर्शन

13.4.4 भारत की विदेश नीति की परिकल्पना के प्रयास

13.4.5 गुटनिरपेक्ष आंदोलन और एक विश्व

#### 13.5 सारांश

#### 13.6 संदर्भ

#### 13.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

---

### 13.0 उद्देश्य

---

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ने एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया, जिसकी विशेषता गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया थी। असंख्य एशियाई और अफ्रीकी देश, जो साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों के शासन के अधीन थे, अब स्वतंत्र थे। गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और उसके निहितार्थ किसी को वैश्विक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

- गैर-उपनिवेशीकरण के कारणों की व्याख्या करना;
- शीत युद्ध ने गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया;
- नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध को कैसे भुनाया, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान करना; तथा
- भारत में साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन ने विदेश नीति को आकार देने में कैसे मदद की।

---

\* डॉ. सॉची रॉय, स्वतंत्र शोधक, न्यूयार्क विश्वविद्यालय, अबू धाबी से जुड़ी हुई

## 13.1 प्रस्तावना

15वीं शताब्दी से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बड़े भूभाग ने गरिमा और मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन को सहा। वे यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपनिवेश बने। अधिकांश स्थानों पर यह प्रक्रिया आमतौर पर यूरोपीय देशों द्वारा व्यापारियों को भेजने और फिर धीरे-धीरे क्षेत्र का राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने के साथ शुरू हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश गैर-यूरोपीय देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय देशों द्वारा शासित हो गए। ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और स्पेनिश आक्रमणकारियों द्वारा मजबूत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए गए थे। इस दौरान उपनिवेश बनाने वाला जापान एकमात्र एशियाई देश था।

मोटे तौर पर गैर-उपनिवेशीकरण को 1945 के बाद साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा अपने पूर्व उपनिवेशों को संप्रभुता स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। कुल मिलाकर गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से सामने आने में दशकों लग गए। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं थी जिसका प्रभाव विश्व राजनीति पर लंबे समय तक रहा। जहां इस प्रक्रिया ने एक तरफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया, वहीं दूसरी ओर इसका परिणाम अक्सर लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और स्थायी प्रतिद्वंद्विता के रूप में सामने आया। इनमें से कई प्रतिद्वंद्विता अभी भी मौजूद हैं और उन्हें समझे बिना विश्व राजनीति को समझा नहीं जा सकता।

### 13.1.1 वैश्विक संदर्भ में उपनिवेशीकरण विरोधी आंदोलनों को समझना

आमतौर पर एक यूरोपीय साम्राज्य का निर्माण न केवल एक देश पर राजनीतिक पकड़ स्थापित करने के लिए किया गया था, बल्कि उस उपनिवेश के पड़ोस में सभी राजनीतिक स्थानों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव को बनाए रखते हुए, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के उपनिवेशों से किसी भी खतरे को दूर करने के लिए किया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका प्राथमिक उद्देश्य सबसे कीमती उपनिवेश पर पकड़ बनाए रखने के लिए भारत की भूमि और सभी समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना था।

हर उपनिवेश का साम्राज्यवाद के साथ अपना अनूठा अनुभव था, हालांकि इन में से अधिकांश के अनुभव लूट, शोषण और कुशासन के थे। अधिकांश देशों में यूरोपीय उपनिवेशवादियों से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कई स्थानीय आंदोलन शुरू हुए (ब्रैडले, 2010)। हालांकि, उपनिवेश राष्ट्रों की विशाल संसाधन शक्ति को देखते हुए यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं थी। परिणामस्वरूप, स्वतंत्रता प्राप्त करने में प्रायः दशकों लग जाते थे।

दुनिया में अधिकांश उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने 1919 के बाद गति प्राप्त की, भले ही उनके संबंधित देशों में वे 1919 से पहले ही शुरू हो गए थे। कुछ वैश्विक घटनाओं ने इसमें योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुडरो विल्सन के आत्म-निर्णय को बढ़ावा देने और राष्ट्र संघ की स्थापना ने कई उपनिवेश विरोधी नेताओं को अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए दबाव देने की उम्मीद में पेरिस आने के लिए एक मंच प्रदान किया। संघ स्वयं कई कारणों से एक असफल संगठन साबित हुआ,

हालाँकि विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्थानीय नेताओं के बीच एकजुटता बढ़ाने की यह गति समाप्त नहीं हुई। समाजवादी तरीके या बोल्शेविक क्रांति के रास्ते की ओर अग्रसर होने वाले नेताओं के बीच बनी एकजुटता से इसे और मदद मिली। ये सम्मेलन अक्सर यूरोप के विभिन्न साम्यवादी मंचों द्वारा आयोजित किए जाते थे। इसके अलावा, आघात और उत्पीड़न के साझा अनुभव के आधार पर अखिल एशियाई और अखिल अफ्रीकी एकजुटता का निर्माण करने का प्रयास किया गया था। इन एकजुटताओं ने आने वाले दशकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 'गैर उपनिवेश विचार की अंतर्राष्ट्रीय धाराएँ' दो महायुद्धों के बीच के वर्षों और महामंदी जैसी अप्रिय घटनाओं के वर्षों में और गहरी हुई (ब्रैडली 2010, पृष्ठ 468)। एम. के. गांधी, हो ची मिन्ह और नेहरू जैसे कुछ नाम वाले बड़े जननेताओं द्वारा अपने-अपने देशों में आंदोलनों को बड़े पैमाने पर दिशा देने के कारण वैश्विक उपनिवेश-विरोधी प्रतिरोध जनसैलाब बन गया।

### 13.2 शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में गैर-उपनिवेशीकरण

किसी देश में उपनिवेश विरोधी आंदोलन की चाहे जब भी शुरुआत हुई, लेकिन अधिकांश एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने 1940 और 1950-60 के दशक के अंत में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता प्राप्त की। ऐसे स्वतंत्र देशों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्य थे। वर्ष 1965 तक यह संख्या बढ़कर 117 हो गई, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हुई (ब्रैडली, 2010: 464)।

जैसा कि स्पष्ट है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद और शीत युद्ध की शुरुआत का समय था। अतः गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को शीत युद्ध की राजनीति के कठिन रास्ते से होकर गुजरना था। इसका मतलब यह नहीं है कि शीत युद्ध ने इस प्रक्रिया को शुरु किया, बल्कि इसने गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में जटिलताओं को बढ़ाया।

गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहीं और की प्रमुख घटनाओं द्वारा उत्प्रेरित थी। पहला, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पूर्व उपनिवेशवादी देश दो भीषण विश्व युद्ध लड़ने के बाद भयावह रूप से कमजोर हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध से बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान और संपत्ति का समग्र विनाश हुआ। युद्ध केवल मैदानों पर ही नहीं, बल्कि कस्बों और शहरों में भी लड़ा गया था। सेनाएँ घनी आबादी वाले शहरी इलाकों को बचाने के लिए उन पर नियंत्रण के लिए उनसे होकर गुजरती थीं। भारी बमबारी और नियमित हवाई हमलों के कारण अधिकांश यूरोप के देश मलबे में तब्दील हो गए थे। अब सब कुछ नए सिरे से बनाया जाना था और अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करना था। यूरोप अपने अंदर देखने के लिए मजबूर हो गया। उनके पास अपने उपनिवेशों को संचालित करने के लिए इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वे अपने उपनिवेशों में लगातार बढ़ते असंतोष और उथल-पुथल को समाप्त कर सकें।

दूसरा, अब दो नई महाशक्ति – यूएसए और यूएसएसआर दुनिया भर में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। वे दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहे, हालाँकि पहले के तरीकों से अलग वे अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते थे। इसलिए, उन्होंने केवल ऐसी सरकारों को बनवाने की कोशिश की, जो उनकी सुरक्षा छतरी के भीतर हों

या गठबंधन में सहयोगी हों। यद्यपि यह अपने आप में जटिल था, लेकिन उस देश पर प्रत्यक्ष शासन करने की पिछली प्रथाओं से अलग था। यूएसए और यूएसएसआर, दोनों ने साम्राज्यवाद विरोधी व्यवस्था को बनाए रखा और इस तरह की प्रवृत्तियों के लिए अक्सर ब्रिटेन और फ्रांस की आलोचना की। गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने उनके हितों को बढ़ाया, क्योंकि इसका अर्थ था कि अब अधिक देश अपने पारंपरिक उपनिवेशवादियों से मुक्त होंगे और बदले में इन महाशक्तियों को इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने का मौका देंगे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो रणनीतिक या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थे। दुनिया भर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों का होना दोनों पक्षों की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था।

### 13.2.1 यूएसए और गैर-उपनिवेशीकरण

जैसा कि वेस्टैड (2017) हमें बताता है, गैर-उपनिवेशीकरण के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका और प्रतिक्रिया, एक बहुत ही अनोखा मामला है। वैधानिक रूप से अधिकांश अमेरिकी उपनिवेश की अवधारणा के विरोध में हैं। आखिरकार उन्होंने भी अंग्रेजों से अपनी आजादी हासिल की है और स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को देने के लिए उन्हें खुद पर गर्व है। एक विचारधारा के रूप में साम्यवाद का अमेरिकी विरोध भी काफी हद तक इस तथ्य पर आधारित था कि उन्होंने साम्यवाद को इनमें से कई मूल्यों के विरोध में देखा, जिन्हें उन्होंने पोषित किया था। कुछ हद तक यूएसए को हमेशा इस बात का डर था कि तीसरी दुनिया के लोग नहीं जानते कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है और उनका झुकाव साम्यवाद की ओर बढ़ सकता है। इसी डर ने अमेरिकी को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, साम्यवाद के डर और शीत युद्ध को जीतने की उसकी इच्छा के कारण अमेरिकी उपनिवेश-विरोधी प्रवृत्ति पर हावी रहे।

### 13.2.2 यूएसएसआर और गैर-उपनिवेशीकरण

वेस्टैड (2017) गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में यूएसएसआर द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमें बताता है। सोवियत संघ का गठन दुनिया भर में पूंजीवाद से लड़ने के सिद्धांतों पर हुआ था। इस मामले में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच एक जटिल संबंध था, क्योंकि एक ने दूसरे को सक्षम किया और दोनों का विरोध जरूरी था। उन्होंने क्रांति को एक अनिवार्यता के रूप में देखा और दुनिया भर के साम्यवादियों के लिए यूएसएसआर में प्रशिक्षण संस्थानों का आयोजन करके इस प्रक्रिया को स्थापित किया।

1921 में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी आफ टाइल्स आफ ईस्ट की स्थापना मास्को में की गई थी। बाकू, इर्कुत्स्क और यहां तक कि ताशकंद में भी इसकी शाखाएँ थीं। इसने कई महत्वपूर्ण नेताओं को प्रशिक्षित किया, जिनमें वियतनाम के हो ची मिन्ह और चीन के डेंग शियाओपिंग के नाम शामिल थे। इसके अलावा, यूएसएसआर द्वारा जन-विरोधी साम्राज्यवादी रुख की वकालत को देखते हुए एशिया और अफ्रीका के बहुत से साम्यवादी और गैर-साम्यवादी विद्यार्थियों ने अध्ययन के लिए सोवियत विश्वविद्यालयों को चुना। यूएसएसआर द्वारा इस तरह के तंत्र का पोषण रणनीतिक अर्थों में किया गया और बाद में संभवतः उपनिवेश विरोधी क्रांति के समर्थन में मदद की, जिसने लंदन और पेरिस जैसे यूरोप के साम्राज्यवादी केंद्रों पर सीधे आघात किया (वेस्टैड, 2017)। 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ

पहली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे सम्मेलनों ने उपनिवेशवाद से लड़ने वाले विभिन्न देशों के नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सुन यात-सेन और अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल थे। इस तरह के सम्मेलनों ने अपने संबंधित देशों में साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए समर्थन और विचारों की तलाश करने वाले कई कार्यकर्ताओं के लिए जुड़ाव के बहुमूल्य अवसर प्रदान किए।

शीत युद्ध के बढ़ने के साथ ही कई नए स्वतंत्र देश योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं की सोवियत शैली की ओर आकर्षित हुए थे, भले ही वे साम्यवादी देश नहीं थे जैसे कि भारत। शीत युद्ध के बढ़ने के साथ ही यह देखा गया कि जिन देशों ने गुटनिरपेक्ष समर्थन का खुले तौर पर समर्थन किया था, वे भी विश्व राजनीति के लिए सोवियत राजनीति पर भरोसा करते थे, खासकर जहां संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल था। औपचारिक रूप से गठबंधन किए बिना यूएसएसआर के लिए भारत की निकटता प्रसिद्ध है। दक्षिण एशिया में भारत का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान CENTO के तहत औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन में था और 1960 के दशक तक चीन के रूप में भारत का अपनी सीमाओं पर एक अतिरिक्त विरोधी मौजूद था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में यह देखते हुए कि यूएसएसआर अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था और चीन के साथ भी संबंध तनावपूर्ण थे, यूएसएसआर के साथ भारत की निकटता एक रणनीतिक समझ थी।

### बोध प्रश्न 1

**नोट :** i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थानों का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई के अंत में देखें।

1) गैर-उपनिवेशीकरण के शुरू होने के क्या कारण थे?

.....  
.....  
.....  
.....

2) गैर-उपनिवेशीकरण को लेकर अमेरिका का क्या रुख था?

.....  
.....  
.....

3) गैर-उपनिवेशीकरण को लेकर यूएसएसआर का क्या रुख था?

.....  
.....  
.....

### 13.3 विश्व राजनीति पर गैर-उपनिवेशीकरण का प्रभाव

नए स्वतंत्र राष्ट्रों का लक्ष्य, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में, न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना, बल्कि समान अधिकार के साथ वैश्विक मामलों में अपनी बात रखने के लिए अपने अधिकार के एक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त करना था। कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के दृष्टिकोण से शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर द्वारा उनके ऊपर दिए गए जोर, औपचारिक उपनिवेशवादियों द्वारा उन पर लगाए गए नियंत्रण से अलग नहीं था। जहाँ तक उनकी बात थी, दोनों स्थितियाँ बहुत अलग नहीं थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसएसआर के नेतृत्व वाले गठबंधनों में शामिल नहीं होने की इच्छा रखने वाले अधिकांश नए स्वतंत्र राष्ट्र तटस्थ रहने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए। वे जानते थे कि इस तरह के सैन्य या राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा होने का मतलब होगा कि पहले से ही दुर्लभ संसाधन शीत युद्ध के उद्देश्यों को बनाए रखने में बर्बाद होंगे और इनका उपयोग आवश्यक विकास कार्यों के लिए नहीं हो पाएगा। हालाँकि, नव-निर्मित या नए स्वतंत्र प्रत्येक देश ने ऐसा महसूस नहीं किया: उदाहरण के लिए पाकिस्तान आधिकारिक रूप से अमेरिका के साथ केंद्रीय संधि संगठन या CENTO में शामिल हो गया।

एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एकजुटता बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन था। इसके बाद 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, जिसने तीसरी दुनिया की एकजुटता को मजबूत करने की कोशिश की, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच तेजी से विभाजित थी। एनएएम का उद्देश्य किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन न करके तीसरी शक्ति के रूप में उभरना था।

#### 13.3.1 नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं का पुनर्रखांकन

गैर-उपनिवेशीकरण प्रक्रिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का पुनर्रखांकन या नए राज्यों का निर्माण है, जैसे कि पाकिस्तान और इजरायल। अफसोस की बात है कि इस राजनीतिक झटके से कई बार विवादों या स्थायी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है, जो क्षेत्रीय या विश्व राजनीति की निरंतर विशेषता बन जाती है (ब्रैडली, 2010)। अनुसंधान से पता चला है कि अधिकांश स्थायी प्रतिद्वंद्विता अक्सर क्षेत्र के सवाल पर उत्पन्न होती हैं (लिकलाइडर, 2005)। किसी राष्ट्र की सुरक्षा या उसकी प्रतिष्ठा के मामले में सीमा को परिभाषित करने के महत्व को देखते हुए, ये संघर्ष दीर्घकाल में हल करने के लिए बहुत मुश्किल साबित होते हैं। ऐसे दो मुद्दे हैं, जो प्रायः एक-दूसरे से सहयोग पाते हैं।

पहला, एशिया और अफ्रीका में कई सीमाएं शासन करने के दौरान यूरोपीय शक्तियों द्वारा खींची गई थीं। इन सीमाओं को चित्रित करने का औचित्य यूरोप में शक्ति संतुलन से अधिक संबंधित था और वास्तविक धार्मिक या नृजातीय वास्तविकताओं से कम था। ये वो सीमाएँ हैं, जो यूरोपीय राष्ट्र द्वारा उपनिवेशों को छोड़कर जाने के बाद भी बनी हुई हैं। दूसरा, जब तक यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इन जमीनों का इस्तेमाल किया, तब तक सीमाएँ बनाए रखी गईं। हालाँकि, जैसे ही उन्होंने छोड़ा बड़े पैमाने पर धार्मिक या नृजातीय हिंसा भड़क गई। कई मामलों में इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक मानचित्र फिर से तैयार हुआ। इसका मतलब यह था कि अधिकांश मामलों में लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद गैर-उपनिवेशीकरण की एक विरासत थी। कई

मामलों में ये सीमा विवाद शीत युद्ध की जटिलताओं में उलझ गए, जिससे वे और मुश्किल बन गए। अरब-इजरायल संघर्ष और भारत-पाक संघर्ष, विशेष रूप से कश्मीर पर, जैसे प्रमुख उदाहरण हैं, जो स्थायी प्रतिद्वंद्विता के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और विश्व राजनीति की एक स्थायी विशेषता बन गए हैं।

### 13.4 उपनिवेशीकरण विरोधी आंदोलन और विदेश नीति के निहितार्थ-भारतीय संदर्भ

ऐसे कई तरीके हैं जिनमें किसी देश का उपनिवेशिक अनुभव उपनिवेशिक राज्य के जाने के बाद भी उसके फैसलों को प्रभावित करना जारी रखता है। अपने उपनिवेशवादियों से स्वतंत्रता कभी भी एक स्वच्छ विराम नहीं है। उपनिवेश की विरासत बनी रहती है और इसे विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। किसी राष्ट्र की राजनीति को समझने के लिए उसके उपनिवेशिक अनुभव की निरंतर छाया का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसी ही एक जगह है, जहाँ इस पर अध्ययन किया जा सकता है, वह है एक राष्ट्र की विदेश नीति। निम्नलिखित भाग में हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति में कितनी प्रासंगिकता है। इसे तटस्थ होने के कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व के विचारों और बाद में नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बदलने के बीच कड़ी के रूप में देखा जा सकता है।

#### 13.4.1 उपनिवेशिक अतीत और इसकी प्रासंगिकता

हीमसाथ और मानसिंह (1971) का तर्क है कि भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद भी बहुत निरंतरता और स्थिरता दिखाती है, हालांकि भारत के पास इस संबंध में अपने उपनिवेशिक अतीत से पूरी तरह से मुक्त होने का विकल्प था। मानसिंह और हीमसाथ बताते हैं कि इस तरह के कदम का कारण यह है कि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मामलों में अर्ध-स्वतंत्र का दर्जा हासिल कर लिया था। औपचारिक रूप से भारतीय नेता ब्रिटिश राजशाही के अधीन थे और अपनी स्वयं की एक अलग विदेश नीति की वकालत नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में नाटकीय परिवर्तन देखा गया। राष्ट्र संघ जैसे असंख्य अंतर्राष्ट्रीय मंच व्यवहार में आने लगे और भारत उनमें से कई में एक उत्साही सदस्य और भागीदार था। भारतीय नेता विश्व के अन्य नेताओं के लगातार संपर्क में थे। संक्षेप में, इन सभी के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता के लगभग 30 साल पहले ही भारत को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ सक्रियता से जुड़ने और स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति चुनने के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त करने की शुरुआती बढ़त मिल गई थी। भारतीय कूटनीति की स्वतंत्रता-पूर्व उत्पत्ति (1992, पृष्ठ 42) को समझने के प्रयास में कीनीलसाइड लिखते हैं, “... भारत राजनयिक प्रतिभा के भंडार और सामान्य विदेश नीति के लक्ष्यों की एक श्रृंखला सहित अपनी कूटनीति के प्रारंभिक अभिविन्यास के साथ उपनिवेशिक शासन से निकला है।” इस मोड़ पर मानसिंह और हीमसाथ (1971) विदेशी संबंधों और विदेश नीति को अलग करते हैं। इसलिए, उनकी समझ के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेश संबंध स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति बन गए।

### 13.4.2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता से पहले विदेशी संबंध

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता-पूर्व विदेश नीति गतिविधियों को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कांग्रेस नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच बातचीत का तरीका होगा। दूसरी, वैचारिक दिशा होगी जिसे कांग्रेस नेताओं ने सोचा था कि स्वतंत्र भारत के पास होना चाहिए। बाहरी दुनिया के साथ भागीदारी के स्तर और विदेश नीति के लिए बढ़ती वैचारिक अवधारणाओं के संदर्भ में विभिन्न चरणों को समझा जा सकता है।

बिपन चंद्र (1989) के अनुसार, प्रथम विश्व युद्ध से पहले राष्ट्रवादी विदेश नीति में तीन रुझानों की व्याख्या की जा सकती है। पहला: अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अन्य देशों के साथ एकजुटता और समर्थन। दूसरा: एशियाई चेतना का उदय और एक सामान्य एशियाई पहचान का अहसास। तीसरा: रुझान साम्राज्यवाद के विकास के पीछे आर्थिक औचित्य की बढ़ती समझ से संबंधित है। 1914 के बाद राष्ट्रवादी विदेश नीति राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध करने और विश्व शांति के लिए सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग की ओर अग्रसर हुई। नेहरू (1927) खुद लिखते हैं कि कैसे, विश्व शांति जैसे बड़े लक्ष्य के सामने, भारत अपनी संप्रभुता के कुछ तत्वों को सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए छोड़ने से मना नहीं करेगा, बशर्ते दूसरे देश भी ऐसा करें।

### 13.4.3 विश्व तक पहुँचने का प्रयास और एकजुटता का प्रदर्शन

दुनिया तक पहुँचने की अपनी शुरुआती कोशिशों में कांग्रेस ने ब्रिटिश समिति का गठन किया। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य भारत के उद्देश्य के लिए इसकी नीतिपरागणता को ब्रिटिश जनता को समझाने के लिए इंग्लैंड में प्रचार करना था। हालांकि, इससे वांछित परिणाम नहीं मिला और 1920 में नागपुर में कांग्रेस द्वारा समिति को समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं द्वारा यह महसूस किया गया कि असहयोग आंदोलन के मंच के माध्यम से घर में प्रभावी कार्रवाई उन्हें इंग्लैंड और दुनिया के अन्य हिस्सों में अधिक प्रचार तब दिला रही थी, जबकि वे पहले की तरह सक्रिय रूप से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे थे। इसलिए, घर में उनकी ऊर्जा और संसाधनों को खर्च करने के संकल्प को और मजबूत किया गया। उसी समय, नेहरू को इस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया था कि चीन, मिस्र, बर्मा, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व के कई अन्य क्षेत्रों में भारतीयों को पसंद नहीं किया जाता था, जहां ब्रिटिश उन्हें ब्रिटिश सेना या पुलिस में जनशक्ति के रूप में ले जाते थे। नेहरू ने सोचा था कि कांग्रेस को इन भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों को विदेशों से हटाने की दिशा में काम करना चाहिए और भारत जैसे उपनिवेशिक उत्पीड़न से पीड़ित राष्ट्रों के साथ सौहार्द और मित्रता का वातावरण स्थापित करना चाहिए।

बिपन चंद्र (1989) बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए विदेशी प्रयासों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बेहद चिंतित थी। चंद्रा (1989) आगे बताते हैं कि भारत में कांग्रेस के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से भारत के पड़ोसी क्षेत्रों के साथ युद्ध छेड़ने और कुछ मामलों में उनके क्षेत्रों को हड़पने की ब्रिटिश नीति को लेकर असंतोष व्यक्त किया। यह पूरी तरह से नया अभ्यास नहीं था। जब 1885



के अंत में बर्मा को हड़प लिया गया तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कृत्य को अनैतिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने द्वितीय एंग्लो-अफगान युद्ध (1878-80) को आक्रामकता का एक बड़ा कारण बताया। 1903 में तिब्बत पर लॉर्ड कर्जन के हमले के दौरान भी हंगामा हुआ। हालाँकि, ऐसी आलोचनाओं ने अब एक सुसंगत और स्पष्ट-दृष्टि वाली नीति का रूप ले लिया।

#### 13.4.4 भारत की विदेश नीति की परिकल्पना के प्रयास

नवंबर 1921 में कांग्रेस ने ब्रिटिश विदेश नीति से स्वतंत्रता की पहली औपचारिक घोषणा-पत्र को अपनाया और इसके माध्यम से कांग्रेस अन्य देशों को यह बताना चाहती थी कि भारत सरकार भारतीय मत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इसकी नीतियों का उद्देश्य भारत को उसकी सीमाओं की रक्षा करने के बजाय अधीन करना है। एक स्वशासित देश के रूप में भारत के पास अपने पड़ोसी या किसी अन्य राज्य को लेकर कोई खाका नहीं था। यह गांधी द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने महसूस किया कि 'स्वराज' के लिए परिपक्व भारत दुनिया को बताने के लिए बाध्य था कि किस तरह का संबंध भारत उनके साथ चाहता था (प्रसाद 1962)। प्रसाद की यह पुस्तक 'द ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी: द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वर्ल्ड अफेयर्स' 1885 से 1947 तक विश्व मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा करती है। कांग्रेस के नेताओं का विचार था कि विश्व की शांति और सुरक्षा पर स्वतंत्र भारत के जो सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं उसे बाल गंगाधर तिलक ने आगे दोहराया है। जॉर्ज क्लेमेंसियो को दिए एक ज्ञापन में तिलक ने कहा था कि एक मजबूत और स्वतंत्र भारत विश्व के लिए स्थिरता का स्रोत होगा। तिलक ने भारत की विदेश और रक्षा नीतियों में ब्रिटेन के साथ मजबूत संबंधों की परिकल्पना की (मेहता, 2009, 213)। इसी तरह का विचार नेहरू ने दिया था, जब उन्होंने दावा किया था कि भारत का प्रतिरोध ब्रिटिश नीतियों और भारत पर उनके वर्चस्व के खिलाफ था, जबकि "भारतीय स्वतंत्रता के आधार पर" ब्रिटिश लोगों के साथ सहयोग का स्वागत किया जाएगा (कपूर, 2011, पृष्ठ 61)।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मुलाकात में कांग्रेस के विभिन्न नेताओं द्वारा जो भूमिका निभाई गई, और ऐसी मुलाकात को जिस विचारधारा ने प्रेरित किया, उसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पश्चिम एशिया, इजरायल और खासकर फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति इस खोज का एक दिलचस्प मामला है, जिस पर प्रमुख नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी थी। कुमारस्वामी (2010) प्रभावी रूप से एम.के. गांधी द्वारा लंबे समय तक निभाई भूमिका को दर्शाते हैं, जिसने बाद में इजरायल और पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित किया। उस क्षेत्र के बारे में गांधी के विचारों में अक्सर उन्हीं विसंगतियों को दर्शाया गया, जो भारत ने बाद के चरण में इजरायल के साथ अपने संबंधों में दिखाई। यहूदियों की स्थिति के प्रति गहरी समझ और सहानुभूति रखते हुए गांधी ने कभी भी इजरायल के निर्माण के लिए फिलिस्तीन विभाजन योजना का औपचारिक समर्थन नहीं किया और इस तरह के कदम के खिलाफ बात की। मध्य पूर्व पर गांधी के विचारों में सूक्ष्मताओं और मजबूरियों को ब्रिक (2008) के काम में विस्तार से वर्णित किया गया है।

जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की मांग शुरू की, उन्हें महसूस हुआ कि स्वतंत्रता की तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह संकल्पना करना था कि स्वतंत्र भारत में किस तरह की विदेश नीति होगी। आगे यह महसूस

किया गया कि अन्य विश्व नेताओं और संगठनों के साथ संबंध बनाना, विशेषकर उन राष्ट्रों के साथ जो उपनिवेशवाद से लड़ रहे थे, एकजुटता बनाने में मदद करेगा, जो उपनिवेशवाद से लड़ने में मिलकर काम कर सकेंगे। इन संपर्कों ने भारत की कूटनीति की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न विश्व नेताओं के बीच बने व्यक्तिगत संबंध असंख्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों (मैकक्वाड, 2020) पर बातचीत के बढ़ते अनुभव के रूप में उभरा। ठाकुर (2017) ने उस प्रभाव को विस्तार से बताया है, जो विदेश नीति पर भारतीय उदारवादियों (ब्रिटिश भारत के राजनयिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा) का स्वतंत्रता के पूर्व के तीन दशकों और उसके बाद भी रहा। इस अनुभव ने भारतीय नेताओं को उस समय के विभिन्न वैश्विक नजरिये और प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों को समझने में मदद की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उन्हें विश्व राजनीति की पेचीदगियों को समझने और स्वतंत्र भारत के लिए विदेश नीति की संकल्पना तैयार करने का मौका देने के लिए पर्याप्त समय दिया। निम्न खंड प्रकाश डालता है कि ये सोच और संकल्पनाएं एक ठोस नीति का रूप कैसे लेती हैं।

### 13.4.5 गुटनिरपेक्ष आंदोलन और एक विश्व

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ों के संदर्भ में, विल्लेट्स (1978) जैसे विद्वानों ने पाया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैचारिक उत्पत्ति के बारे में केवल 1961 में ही नहीं, बल्कि 1940 के दशक में कुछ तर्क दिए गए, जो कि अलग-अलग समय में यह अलग-अलग नामों से जाना गया। यहाँ तक कि विल्लेट्स खुद को इस तरह के दावे की अवहेलना करते हैं, ऐसा करने का उनका कारण पूरी तरह यकीनी नहीं है, और बहस के लिए खुला है। ऐसा करने में वे तटस्थता के साथ गुटनिरपेक्षता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं जिसके खिलाफ मूर्ति (1964) और राघवन (2010) जैसे अन्य विद्वानों ने भी तर्क दिया है। हालाँकि, इस कथन के दावे में कुछ सार हो सकता है कि गुटनिरपेक्षता के विचार आजादी के पहले से मौजूद थे, क्योंकि बिमला प्रसाद (1962, पृ. 28) बताते हैं कि 7 सितंबर 1946 को नेहरू ने घोषणा की थी कि भारत को दुनिया में एक दूसरे के विरोधी शक्ति समूहों से यथासंभव दूर रहना है। इसलिए, यह सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखने का प्रयास था। यह देखते हुए कि बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे यही विचारधारा थी, 1947 से पहले अपनी विचारधारा की जड़ें देखने और उसे आगे खोजने के अभिकथन मौजूद थे। मनु भगवान (2012) का तर्क है कि गुटनिरपेक्षता “केवल नेहरू के, बड़े लक्ष्य का एक तत्व था, जो एक विश्व का विचार था। इस समझ से गुटनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ तटस्थ होना नहीं था, बल्कि एक सच्चे गांधीवादी अर्थ में यह दो युद्धरत गुटों के साथ समान रूप से जुड़ना था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ ही विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। भगवान (2012) बताते हैं कि यह एक मौका था जो नेहरू द्वारा गांधी के अहिंसा के संदेश को ‘एक विश्व’ के रूप में दुनिया के सामने ले जाने का एक मौका था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के दौरान विजया लक्ष्मी पंडित इस उद्देश्य की सबसे प्रबल प्रस्तावक और वकील थीं। जैसा कि मनु भगवान बताते हैं कि ‘एक विश्व’ की अवधारणा मानवाधिकारों पर वैश्विक अभिकथनों को प्रस्तुत करने में प्रभावशाली थी।

ऊपर की चर्चा से यह देखा जा सकता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के कई मूल सिद्धांत इसके उपनिवेशिक अनुभव से उपजे थे। एक उपनिवेश के रूप में वशीभूत होने का कार्य और एक राष्ट्र किस तरह से उससे लड़ने का फैसला करता

है, यह परिभाषित करने में मदद करती है कि वह देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कहाँ देखता है।

## बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थानों का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तर के सुझावों के लिए इकाई के अंत में देखें।

1) नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध के दौरान अपना संचालन कैसे किया?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2) क्या गैर-उपनिवेशीकरण और संघर्षों के बीच कोई संबंध है?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3) गैर-उपनिवेशीकरण विरोध ने भारत की विदेश नीति को कैसे आकार दिया?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

## 13.5 सारांश

---

कई उपनिवेशिक देशों ने 1940 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक के बीच स्वतंत्रता प्राप्त की। यह कई कारकों का परिणाम था, जिसमें कुछ प्रमुख कारक शाही यूरोपीय शक्तियों का कमजोर होना और शीत युद्ध की शुरुआत थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर ने विश्व राजनीति पर हावी होने की कोशिश की और अन्य देशों की राजनीति में दोनों ने अपने अलग-अलग कारणों से साम्राज्यवाद विरोधी रुख अपनाया और इसलिए सीधे उन पर शासन करने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद, अगर उनके अपने वैश्विक एजेंडे के अनुकूल रहा तो उन्होंने अन्य देशों के मामलों में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया।

इन नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने दुनिया में अपनी जगह बनाई और विश्व मामलों को सक्रिय रूप से आकार देना शुरू किया। राजनीति के उनके अपने ब्रांड की एक खासियत यह थी कि उन्होंने दोनों में से किसी भी महाशक्ति के दल में शामिल होने के बजाय

गुटनिरपेक्षता के विकल्प की वकालत की। दो शत्रुतापूर्ण दलों में दुनिया का विभाजन नए स्वतंत्र राष्ट्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल नहीं था और इसलिए कई देशों ने औपचारिक रूप से किसी भी दल के साथ गठबंधन करने का विकल्प नहीं चुना। गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने अक्सर अव्यवस्थित संघर्षों और स्थायी प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया। अक्सर ये एक नए राज्य के निर्माण के साथ गैर-उपनिवेशीकरण की जटिलता के परिणामस्वरूप सीमा विवाद से बाहर उभरे।

इस इकाई ने भारतीय उदाहरण को लेकर एक देश की विदेश नीति पर साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलनों के प्रभाव का वर्णन किया। गैर-उपनिवेशीकरण का परिणाम किसी देश के अतीत से उसका स्पष्ट छुटकारा नहीं हो सकता है। इसका परिणाम यह है कि उपनिवेश होने और उपनिवेशवादियों से लड़ने का अनुभव देश की आजादी के बाद की नीति को भी आकार देने में मदद करता है। इसलिए, यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि किसी देश का पूर्व-उपनिवेशिक अतीत किसी राष्ट्र के उपनिवेश के बाद के वर्तमान से कैसे संबंधित है।

---

### 13.6 संदर्भ

---

भगवान, मनु. (2012). *पीसमेकर : इण्डिया एण्ड दि क्वेस्ट फॉर वन वर्ल्ड*. न्यू डेहली. हार्प कोलिंस.

ब्रैडली, मार्क फिलिप. (2010). 'डिकोलोनाइजेशन, दि ग्लोबल साउथ एण्ड दि कोल्ड वार, 1919-1962, इन मेल्विन पी. लेफ्लर एण्ड ऑड आर्ने वेस्टाड. (एडिटर्स). *दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ दि कोल्ड वार*. वॉल्यूम-1. पृ. 464-485. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

ब्रिक, सिमोन पैन्टर. (2008). *गांधी एण्ड दि मिडिल ईस्ट : जेम्स. अरब्स एण्ड इम्पीरियल इंटररेस्ट*. लन्दन : आई. बी. टॉरिस एण्ड कं. लिमिटेड.

चन्द्र बिपन. एट आल. (1989). *इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857-1947*. न्यू डेहली : पेंगुइन बुक्स.

हिमसाथ सी. एण्ड एस मानसिंह. (1971). *ए डिप्लोमैटिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इण्डिया*. बॉम्बे : अलाइड पब्लिशर्स.

कीन्लीसाइड, टी.ए. (1992). 'डिप्लोमैटिक ऐप्रेंटिसशिप : प्रि-इंडिपेंडेंस ओरिजिन्स ऑफ इण्डियन डिप्लोमैसी एण्ड इट्स रिलिवेंस फॉर दि पोस्ट-इंडिपेंडेंस फौरेन पॉलिसी'. इन विरेन्दर ग्रोवर. (एडिटर्स). *इंटरनेशनल रिलेशंस एण्ड फौरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया : इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस एण्ड इंडियाज फौरेन पॉलिसी*. वॉल्यूम-1. न्यू डेहली. डीप एंड डीप पब्लिकेशंस.

लीक्लिडर, आर. (2005). *कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ लांग वार्स, इन सी.ए. क्रूकर, एफ. ओ. एण्ड पी. आल (एडिटर्स). ग्रास्पिंग दि नैटल : ऐनालाइजिंग केसेज ऑफ इंटरैक्टिव कॉन्फ्लिक्ट*. पृ. 33-46. वाशिंगटन डी.सी. : यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस प्रेस.

मैक्क्वेड, जोसेफ. (2020). *बियोण्ड ऐम इम्पीरियल फौरेन पॉलिसी : इंडिया ऐट दि लीग ऑफ नेशंस. 1919-1946. दि जर्नल ऑफ इम्पीरियल एण्ड कॉमनवेल्थ हिस्ट्री*. 48-(2), 263-295.

मेहत, प्रताप भानू. (2009). स्टिल अण्डर नेहरूज शैडो, दि अब्सेंस ऑफ फौरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स इन इंडिया. *इंडिया रिव्यू* 8(3), 209-233.

मूर्ती, के. (1964). *इंडियन फौरेन पॉलिसी*. कलकत्ता : साइंटिफिक बुक एजेंसी.

नेहरू, जवाहरलाल. (1927). ए फौरेन पॉलिसी फॉर इंडिया, ए. आई. सी. सी. फाईल नं.8, 1927, पृ.1-27. एन. एम. एम. एल. ऐज रिप्रोड्युज इन, *सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू : ए प्रोजेक्ट ऑफ दि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फण्ड*. वाल्यूम-2, (1972). न्यू डेहली : ओरियंट लॉगमैन.

प्रसाद, बिमला (1962). *दि ऑरिजिन ऑफ इंडियन फौरेन पॉलिसी : दि इण्डियन नैशनल कांग्रेस एण्ड वर्ल्ड अफेयर्स, 1885-1947*. कलकत्ता : बुकलैण्ड प्राइवेट लिमिटेड.

ठाकुर, विनीत. (2017). लिबरल, लिमिनल एण्ड लॉस्ट : इंडियाज फर्स्ट डिपलॉमेट्स एण्ड दि नरेटिव ऑफ फौरेन पॉलिसी. *दि जर्नल ऑफ इम्पीरियल एण्ड कॉमनवेल्थ हिस्ट्री*. 45(2), 232-258.

वैटेस, बेर्नार्ड. (1999). *योरोप एण्ड दि थर्ड वर्ल्ड : फ्रॉम कोलोनाइजेशन टू डि कोलोनाइजेशन, सी-1500-1998*. लण्डन : पालग्रेव मैकमिलन.

वेस्टाड, ऑड आर्ने. (2007). *दि ग्लोबल कोल्ड वार : थर्ड वर्ल्ड इण्टरवेंशंस एण्ड दि मेकिंग ऑफ अवर टाइम्स*. कैम्ब्रिज न्यू यॉर्क : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

वेस्टाड, ऑड आर्ने. (2017). *दि कोल्ड वार : ए वर्ल्ड हिस्ट्री*. न्यू यॉर्क : बेसिक बुक्स.

विलेट्स, पी. (1978). *दि नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट : दि ओरिजिन्स ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड अलाइन्स*. न्यू यॉर्क : निकोलस पब्लिशिंग.

## 13.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

### बोध प्रश्न 1

- 1) गैर-उपनिवेशीकरण के शुरुआत के मुख्यतः तीन कारण थे। पहला था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शाही यूरोपीय देशों का कमजोर होना। दूसरा था, विदेशी शासन के खिलाफ कई देशों में उपनिवेशवाद विरोधी मजबूत आंदोलन। तीसरा, शीत युद्ध की शुरुआत के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने ही अपने रणनीतिक हितों में देशों पर सत्तारूढ़ होने का विचार नहीं किया। इसके बजाय वे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर रखना चाहते थे।
- 2) अधिकांश अमेरिकियों ने उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं किया। हालांकि, उनके लिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण था कि नव स्वतंत्र उपनिवेशों में साम्यवाद भी ना फैले।
- 3) यूएसएसआर में समझ यह थी कि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से उपजा था, जो कि पूंजीवाद से गहनता से जुड़ा था। इसलिए, उन्होंने ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं किया। हालांकि, उन्होंने महसूस किया कि अन्य स्थानों पर भी क्रांति को शुरू करना महत्वपूर्ण था और इसे सक्रिय करने के लिए साधन दिए।

## बोध प्रश्न 2

- 1) नव स्वतंत्र देशों ने किसी भी महाशक्ति के गुट या दल में शामिल न होने का चुनाव करके और अपना संगठन बनाकर शीत युद्ध से बचे रहे। इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
- 2) हाँ, गैर-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया क्षेत्रीय विवादों को जन्म देती है, जो अक्सर असाध्य हो जाते हैं।
- 3) यह स्वतंत्रता के संघर्ष का वक्त था, जब भारतीय नेताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए एक विदेश नीति की आवश्यकता को महसूस किया। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एकजुटता और विदेश नीति में भारत की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बनाए रखने पर बहुत जोर दिया गया।



ignou  
THE PEOPLE'S  
UNIVERSITY